

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	कार्तिक 1, शुक्रवार, शाके 1942-अक्टूबर 23, 2020 <i>Kartika 1, Friday, Saka 1942-October 23, 2020</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 22, 2020

संख्या प. 11(24)गृह-10/2018 :-यतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (दाण्डिक) 156/2016 महेन्द्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में आदेश दिनांक 5 दिसम्बर, 2018 द्वारा साक्षी संरक्षण कार्यक्रम के लिए स्कीम बनाने हेतु निदेशित किया है।

अतः साक्षियों की सुविधा, सहूलियत और न्यायिक व्यवस्था में परिसाक्ष्य के बारे में संभावित धमकी से साक्षी को संरक्षण देने या अभित्रास या प्रतिशोध के भय के बिना विधि के प्रवर्तन और अन्वेषण के साथ सहयोग करने के प्रति सम्यक् ध्यान दिये जाने के लिए, साक्षी संरक्षण की आवश्यकताओं के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य में साक्षियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात्:-

राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- (1) इस स्कीम का नाम “राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020” है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

भाग - I

2. परिभाषाएं:-

- (क) “संहिता” से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) अभिप्रेत है;
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में, सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त और सदस्य-सचिव के रूप में सहायक निदेशक अभियोजन वाली स्थायी समिति अभिप्रेत है;
- (ग) “साक्षी की पहचान छिपाया जाना” से अन्वेषण, विचारण और विचारण-पश्चात् के दौरान किसी भी रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नाम, पता और अन्य विशिष्टियों के प्रकाशन, जो साक्षी की पहचान दर्शित कर सकें, का प्रतिषेध किया जाना सम्मिलित और अभिप्रेत है;
- (घ) “जिला विधिक सेवा प्राधिकरण” से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं.39) की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ङ) “कुटुम्ब के सदस्य” में साक्षी के माता-पिता/संरक्षक, पति या पत्नी, लिव-इन पार्टनर, भाई-बहन, संतान, पौत्र-पौत्री सम्मिलित हैं;
- (च) “प्ररूप” से इस स्कीम से संलग्न ‘साक्षी संरक्षण आवेदन प्ररूप’ अभिप्रेत है;

(छ) “सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ज) “कैमरा कार्यवाही” से ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं जहां सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय केवल उन व्यक्तियों को जिनका संरक्षण आवेदन की सुनवाई और विनिश्चय के समय या न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के लिए उपस्थित होना आवश्यक हो, को न्यायालय में अनुज्ञात करे।

(झ) “लाइव लिंक” से अभिप्रेत है और इसमें लाइव विडियो लिंक या अन्य ऐसी व्यवस्था सम्मिलित है जिसके द्वारा कोई साक्षी, जब वह न्यायालय कक्ष से अनुपस्थित हो, मामले में अभिसाक्ष्य दे सके या सक्षम प्राधिकारी से अंतःक्रिया कर सके;

(ञ) “साक्षी संरक्षण उपाय” से स्कीम के खण्ड 7 में लिखित उपाय अभिप्रेत हैं;

(ट) “अपराध” से वे अपराध अभिप्रेत हैं जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या सात वर्ष तक के या अधिक के कारावास से और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ और 509 के अधीन दण्डनीय हों;

(ठ) “राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण” से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 6 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) “धमकी विश्लेषण रिपोर्ट” से साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्य को धमकी मिलने की गंभीरता और विश्वसनीयता के संबंध में मामले का अन्वेषण करने वाले जिले के पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट अभिप्रेत है। इसमें साक्षी और उसके कुटुम्ब को उनके जीवन, ख्याति या संपत्ति को दी गयी धमकी की प्रकृति और विस्तार का विश्लेषण करने के अतिरिक्त धमकी देने वाले व्यक्तियों के आशय, हेतु और धमकी के क्रियान्वयन के साधनों के बारे में विनिर्दिष्ट ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा।

यह विनिर्दिष्ट साक्षी संरक्षण उपाय, जो कि मामले में किये जाने योग्य हों, का सुझाव देने के अतिरिक्त संभावित धमकी को भी वर्गीकृत करेगी;

(ढ) “साक्षी” से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी भी अपराध के बारे में जानकारी या दस्तावेज रखता हो;

(ण) “साक्षी संरक्षण आवेदन” से साक्षी संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए विहित प्ररूप में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसके सदस्य-सचिव के द्वारा साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्य, उसके सम्यक् रूप से लगाये गये काउन्सलर या संबंधित अन्वेषण अधिकारी/एस.एच.ओ./संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(त) “साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ” से अपर पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला पुलिस का प्रकोष्ठ अभिप्रेत है जिसे स्कीम को क्रियान्वित करने का कर्तव्य समनुदिष्ट किया गया हो;

राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ की अध्यक्षता अपर महानिदेशक, पुलिस (अपराध) द्वारा पुलिस मुख्यालय में की जाएगी;

(थ) “साक्षी संरक्षण निधि” से इस स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन के दौरान उपगत खर्चों को वहन करने के लिए सृजित निधि अभिप्रेत है;

(द) “साक्षी संरक्षण आदेश” से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा देते हुए, पारित आदेश अभिप्रेत है।

भाग- II**3. संभावित धमकी के अनुसार साक्षियों के प्रवर्ग:-**

प्रवर्ग 'क': जहां धमकी का विस्तार अन्वेषण/विचारण के दौरान या उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के जीवन तक हो।

प्रवर्ग 'ख': जहां धमकी का विस्तार अन्वेषण/विचारण के दौरान/उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों की सुरक्षा, ख्याति या संपत्ति तक हो।

प्रवर्ग 'ग': जहां धमकी मामूली हो और अन्वेषण/विचारण के दौरान/उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों की ख्याति या संपत्ति के उत्पीड़न और अभिवासा तक विस्तारित हो।

4. राज्य साक्षी संरक्षण निधि:- (1) एक निधि अर्थात् साक्षी संरक्षण निधि होगी, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन के दौरान उपगत खर्चों और अन्य संबंधित व्ययों की पूर्ति की जायेगी।

(2) साक्षी संरक्षण निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

i. वार्षिक बजट में किये गये बजटीय आबंटन;

ii. न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा साक्षी संरक्षण निधि में जमा करने के लिए अधिरोपित/आदेशित खर्चों की रकम की प्राप्ति;

iii. अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/परोपकारी/पूर्त संस्थाओं/संगठनों और सरकार द्वारा अनुज्ञाप्राप्त व्यष्टियों द्वारा सदान/अंशदान;

iv. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन अंशदान की गई निधि।

(3) उक्त निधि गृह विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।

5. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन का फाइल किया जाना:- इस स्कीम के अधीन संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित जिले में जहां अपराध किया गया है, विहित प्ररूप में, समर्थक दस्तावेजों, यदि कोई हों, के साथ इसके सदस्य-सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया जा सकेगा।

6. आवेदन पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया:-

(क) जैसे ही विहित प्ररूप में आवेदन, सक्षम प्राधिकारी के सदस्य-सचिव को प्राप्त हो जाये, तो वह तुरन्त धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मंगवाने के लिए जिले के अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप-अधीक्षक/जिले के अपर पुलिस उपायुक्त/पुलिस सहायक आयुक्त या संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. को आदेश पारित करेगा;

(ख) आसन्न धमकी के कारण उस मामले में अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए, सक्षम प्राधिकारी आवेदन के लम्बित रहने के दौरान साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के संरक्षण के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा:

परन्तु कोई भी बात पुलिस को आवेदक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के जीवन को गंभीर और आसन्न धमकी के मामले में तुरन्त संरक्षण उपलब्ध कराने से प्रवारित नहीं करेगी;

(ग) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए शीघ्र तैयार की जाएगी और यह आदेश की प्राप्ति से पांच कार्य दिवस के भीतर-भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास पहुंचेगी;

(घ) धमकी विश्लेषण रिपोर्ट संभावित धमकी को वर्गीकृत करेगी और साक्षी या उसके कुटुम्ब को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सुझावात्मक संरक्षण उपाय भी सम्मिलित करेगी;

(ङ) साक्षी संरक्षण के लिए आवेदन पर कार्यवाही करते समय सक्षम प्राधिकारी, साक्षी और/या उसके कुटुम्ब के सदस्यों/नियोजकों या किसी भी अन्य व्यक्ति, जो उचित समझा जाये, से भी अधिमानतः व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव नहीं हो तो इलैक्ट्रॉनिक साधनों से संपर्क करेगा, जिससे कि साक्षी की संरक्षण आवश्यकताओं को अभिनिश्चित किया जा सके;

(च) साक्षी संरक्षण आवेदन पर समस्त सुनवाई पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए सक्षम प्राधिकारी के कक्ष में कैमरा कार्यवाही में की जायेगी;

(छ) पुलिस प्राधिकारियों से धमकी विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति से पांच कार्य दिवस के भीतर-भीतर आवेदन का निपटारा किया जायेगा;

(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश राज्य या, यथास्थिति, जिले के साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। समस्त साक्षी संरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर का होगा:

तथापि, पहचान के परिवर्तन या/और पुनर्वास के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश, राज्य सरकार की अनुज्ञा से पुलिस मुख्यालय में राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा;

(i) साक्षी संरक्षण आदेश पारित कर दिये जाने पर, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ एक मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

(ii) ऐसे मामलों में जिनमें सक्षम प्राधिकारी को यह लगता है कि साक्षी संरक्षण आदेश को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है या इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और विचारण के पूर्ण होने पर, एक नई धमकी विश्लेषण रिपोर्ट अपर पुलिस अधीक्षक /पुलिस उप-अधीक्षक/जिला अपर पुलिस उपायुक्त/ सहायक जिला पुलिस आयुक्त या संबंधित पुलिस थाने के एस.एच.ओ. से मंगवाई जायेगी।

7. संरक्षण उपायों के प्रकार.- आदिष्ट साक्षी संरक्षण उपाय धमकी के आनुपातिक और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होंगे और एक बार में तीन महीने से अधिक के लिए नहीं होंगे। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे:

(क) यह सुनिश्चित करना कि साक्षी और अभियुक्त, अन्वेषण या विचारण के दौरान एक-दूसरे के सामने न आयें।

(ख) मेल और टेलिफोन कॉलों की मानीटरी करना।

(ग) साक्षी के टेलीफोन नंबर परिवर्तित करने के लिए या उसे असूचीबद्ध टेलीफोन नंबर समनुदेशित करने के लिए टेलीफोन नंबर कंपनी के साथ व्यवस्था करना।

(घ) साक्षी के घर में सुरक्षा उपकरण जैसे कि सुरक्षा दरवाजे, सीसीटीवी, अलार्म, तारबंदी, इत्यादि का लगाना।

(ङ) साक्षी को उसके परिवर्तित नाम या वर्ण से निर्दिष्ट करके उसकी पहचान का छिपाया जाना।

(च) साक्षी के लिए आपात में संपर्क किया जाने वाला व्यक्ति।

(छ) साक्षी के घर के चारों तरफ गहन सुरक्षा, नियमित गश्ती।

(ज) किसी नातेदार के घर या किसी नजदीकी कस्बे में आवास का अस्थायी परिवर्तन।

(झ) न्यायालय में जाने और वहां से आने के दौरान अनुरक्षा देना और सुनवाई की तारीख के लिए सरकारी यान या राज्य पोषित परिवहन की व्यवस्था करना।

(ज) कैमरे में विचारण का संचालन।

(ट) कथन और अभिसाक्ष्य के अभिलेखन के दौरान समर्थक व्यक्ति की उपस्थिति को अनुज्ञात करना।

(ठ) विशेष रूप से डिजाइन किये हुए भेद्य साक्षी न्यायालय कक्ष जिसमें कि साक्षी के चेहरे की छवि को उपांतरित करने और साक्षी की आवाज के श्रव्य गृहित संकलन को उपांतरित करने के लिए, जिससे कि वह पहचाना/पहचानी न जा सके के विकल्प सहित, साक्षी और अभियुक्त के लिए अलग-अलग रास्तों के अतिरिक्त विशेष व्यवस्थाएं करना जैसे कि लाइव वीडियो लिंक, एक तरफा दर्पण और स्क्रीन हों।

(ड) बिना स्थगन के दिन-प्रतिदिन के आधार पर विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य के त्वरित अभिलेखन को सुनिश्चित करना।

(ढ) साक्षियों को साक्षी संरक्षण कोष में से पुनर्वास, निर्वाह या नये व्यवसाय/वृत्ति प्रारंभ करने के लिए समय-समय पर कालिक वित्तीय सहायता/अनुदान, जैसा आवश्यक समझा जाये, अधिनिर्णीत करना।

(ण) संरक्षण उपायों का कोई भी अन्य रूप जो आवश्यक समझा जाये।

8. मानीटरी और पुनर्विलोकन.- एक बार संरक्षण आदेश पारित हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी इसके कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा और मामले में प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्टों के निबंधनों के अनुसार इसे पुनरीक्षित कर सकेगा। तथापि, सक्षम प्राधिकारी साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर संरक्षण आदेश का त्रैमासिक आधार पर पुनर्विलोकन करेगा।

9. पहचान का संरक्षण.- (1) किसी भी गंभीर अपराध के अन्वेषण या विचारण के दौरान, पहचान संरक्षण चाहने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसके सदस्य-सचिव के माध्यम से विहित प्ररूप में फाइल किया जा सकेगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी का सदस्य-सचिव धमकी विश्लेषण रिपोर्ट को मंगवायेगा। सक्षम प्राधिकारी साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति का, जो वह उचित समझे, परीक्षण करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचान संरक्षण आदेश पारित किया जाना आवश्यक है या नहीं।

(3) आवेदन की सुनवाई के दौरान साक्षी की पहचान किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जायेगी जिससे कि साक्षी की पहचान संभाव्य हो। सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदन का निपटारा कर सकेगा।

(4) एक बार जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी की पहचान संरक्षण के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करना कि ऐसे साक्षी/उसके कुटुम्ब के सदस्यों के नाम/माता-पिता/उपजीविका/पता/अंकीय पदचिन्हों सहित, की पहचान पूर्णतः संरक्षित है, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व होगा।

(5) जब तक सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन किसी साक्षी की पहचान संरक्षित है, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे उपलब्ध करवायेगा जिससे आपात के मामले में साक्षी द्वारा संपर्क किया जा सके।

भाग- iv

10. पहचान का परिवर्तन.- समुचित मामलों में, जहां साक्षी की ओर से पहचान में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाता है और धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी की नई पहचान प्रदान करने के लिए विनिश्चय लिया जा सकता है।

नई पहचान प्रदान करने में नया नाम/वृत्ति/माता-पिता और शासकीय एजेंसियों द्वारा प्रतिग्राह्य समर्थित दस्तावेज उपलब्ध करवाना सम्मिलित है। नई पहचान साक्षी को विद्यमान शैक्षिक/वृत्तिक/सांपत्तिक अधिकारों से वंचित नहीं करेगी।

भाग- v

11. साक्षियों का पुनर्वास.- समुचित मामलों में जहां साक्षी की ओर से पुनर्वास के लिए अनुरोध किया जाता है और धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी के पुनर्वास के लिए निर्णय लिया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकारी साक्षी के पुनर्वास के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/संघ के क्षेत्र में साक्षी की सुरक्षा, कल्याण और भलाई को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित स्थान का आदेश पारित कर सकेगा। व्यय साक्षी संरक्षण कोष द्वारा वहन किये जायेंगे।

भाग-vi

12. साक्षियों को इस स्कीम से अवगत कराया जाना.- अन्वेषण अधिकारी/न्यायालय प्रत्येक साक्षी को “साक्षी संरक्षण स्कीम” के होने और इसकी मुख्य बातों के बारे में सूचना देगा व इस स्कीम का व्यापक प्रचार करेगा।

13. अभिलेखों की गोपनीयता और परिरक्षण.- (1) पुलिस, अभियोजन विभाग, न्यायालय कर्मचारीवृंद, दोनों पक्षकारों के वकीलों सहित समस्त पदधारी पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में कोई भी अभिलेख, दस्तावेज या सूचना किसी भी परिस्थिति में, विचारण न्यायालय/अपील न्यायालय में और वह भी लिखित आदेश के सिवाय किसी भी रीति से किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जायेगी।

(2) इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित समस्त अभिलेख ऐसे समय तक परिरक्षित रखे जायेंगे जब तक कि संबंधित विचारण या उसकी अपील न्यायालय के समक्ष लंबित है। अंतिम न्यायालय की कार्यवाहियों के निपटारे के एक वर्ष पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों की हार्ड प्रतियां उनकी स्कैन की गयी सॉफ्ट प्रतियों के परिरक्षण के बाद हटायी जा सकेंगी।

14. व्ययों की वसूली.- यदि साक्षी द्वारा मिथ्या परिवाद दाखिल किया जाता है, राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ सरकार की अनुज्ञा से साक्षी संरक्षण कोष से उपगत खर्चों की वसूली के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर सकता है।

15. पुनर्विलोकन.- यदि साक्षी या पुलिस अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों से 15 दिन के भीतर-भीतर पुनर्विलोकन आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

16. निरसन और व्यावृत्तियां.- राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2018 इसके द्वारा निरसित की जाती है। ऐसा निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमित और की गयी किसी बात या की गयी किसी

कार्रवाई या की गयी समझी गयी किसी बात या की गयी समझी गयी किसी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
एन.एल.मीना,
शासन सचिव गृह

राजस्थान साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020
के अधीन साक्षी संरक्षण आवेदन
(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

प्रेषिति,

सक्षम प्राधिकारी,
राजस्थान.....

निम्नलिखित के लिए आवेदन.

1. साक्षी संरक्षण
2. साक्षी पहचान संरक्षण
3. नवीन पहचान
4. साक्षियों का स्थान परिवर्तन

1- साक्षी की विशिष्टियां (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरा जाये):-

- (1) नाम
- (2) आयु
- (3) लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)
- (4) पिता/माता का नाम
- (5) निवास का पता
- (6) साक्षी के कुटुम्ब के सदस्य, जिसे धमकियां प्राप्त हो रही हैं या महसूस हो रही हैं, का नाम और अन्य विशिष्टियां
- (7) संपर्क ब्यौरा (मोबाइल/ई-मेल)

2 दाण्डिक मामले की विशिष्टियां:-

- (1) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.:-
- (2) धारा के अधीन:-
- (3) पुलिस थाना:-
- (4) जिला:-
- (5) दैनिक डायरी सं. (यदि प्र.सू.रि.अब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं की गयी है)
- (6) दाण्डिक मुकदमा सं. (निजी परिवाद के मामले में)

3. अभियुक्त की विशिष्टियां:- (यदि उपलब्ध/ज्ञात है)

- (1) नाम
- (2) पता
- (3) दूरभाष नं.
- (4) ई-मेल आईडी

4. धमकियां देने वाले/संदिग्ध व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियां:-

5. धमकी महसूस करने की प्रकृति।

विनिर्दिष्ट तारीख, स्थान, ढंग और प्रयुक्त शब्दों सहित कृपया उस

मामले में प्राप्त या महसूस की गयी धमकी संक्षिप्त ब्यौरा दें:-

6. साक्षी द्वारा/के लिए प्रार्थना किये गये साक्षी संरक्षण उपायों की
प्रकृति:-

7. अंतरिम अत्यावश्यक साक्षी संरक्षण आवश्यकताओं के ब्यौरे,
यदि अपेक्षित हो।

साक्षी अपने हस्ताक्षर से एक पृथक वचनबंध फाइल करेगा/करेगी कि वह सक्षम प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट/साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेगा/करेगी। आवेदक/साक्षी अतिरिक्त सूचना देने के लिए अतिरिक्त पत्रों का उपयोग कर सकता है।

दिनांक:

स्थान:

(हस्ताक्षर सहित पूरा नाम)

वचनबंध

1- मैं वचन देता/देती हूं कि मैं सक्षम प्राधिकारी और राज्य के गृह विभाग और साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का पूर्णतः सहयोग करूंगा/करूंगी।

2- मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

3- मैं समझता/समझती हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना के मिथ्या पाये जाने की दशा में, सक्षम प्राधिकारी को इस स्कीम के अधीन साक्षी संरक्षण निधि में से मुझ पर उपगत व्ययों को वसूलने का अधिकार आरक्षित है।

दिनांक:

स्थान:

(हस्ताक्षर सहित पूरा नाम)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, October 22, 2020

NO. F.11(24)Home-10/2018 :-Whereas, Hon'ble Supreme Court in Writ Petition 156/2016 Mahindra Chawla & others vs Union of India & others Order dated December 5, 2018 has directed to frame scheme for witness protection program,

Therefore, in order to give due respect to the witnesses convenience, comfort and to give protection to witness from potential threat regarding testimony in a judicial setting or to co-operate with law enforcement and investigation without fear of intimidation or reprisal, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following Scheme for protection of witnesses in the state of Rajasthan, while taking a holistic approach to witness protection needs, namely:-

The Rajasthan Witness Protection Scheme, 2020

- 1. Short title, extent and commencement.-** (1) The Scheme shall be called “Rajasthan Witness Protection Scheme, 2020;
- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan;
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Part-I

2. DEFINITIONS.-

- (a) "**Code**" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No.2 of 1974);
- (b) "**Competent Authority**" means a standing committee in District chaired by District and session Judge, Superintendent of Police / Deputy Commissioner, as its member and Assistant Director Prosecution as its Member Secretary ;
- (c) "**Concealment of Identity of Witness**" means and includes any condition prohibiting publication or revealing, in any manner, directly or indirectly, of the name, address and other particulars which may lead to the identification of the witness during investigation, trial and post-trial stage ;
- (d) "**District Legal Services Authority**" means the District Legal Services Authority constituted under section 9 of the Legal Service Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987);
- (e) "**Family Member**" includes parents/ guardian spouse, live in partner siblings, children, grand children of the witness;
- (f) "**Form**" means “Witness Protection Application Form” appended to this Scheme;
- (g) "**Government**" means the State Government of Rajasthan;
- (h) "**In Camera Proceedings**" means proceedings wherein the competent Authority/court allows only those persons who are necessarily to be present while hearing and deciding the witness protection application or deposing in the Court;
- (i) "**Live Link**" means and include a live video link or other such arrangement whereby a witness, while absent in the court room for deposing in the matter or interacting with the competent Authority ;
- (j) "**Witness Protection Measures**" means measures spelt out in clause 7 of the scheme;
- (k) "**Offences**" means those offences which are punishable with death or life imprisonment or an imprisonment up to seven years and above and also Offences punishable under section 354, 354A, 354B, 354C, 354D and 509 of IPC;
- (l) "**State Legal Services Authority**" means the Authority constituted under section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No.39 of 1987);
- (m) "**Threat Analysis Report**" means a detailed report prepared and submitted by the Deputy Commissioner of Police/ Superintendent of Police in the District investigation the case with regard to the seriousness and credibility of the threat perception to the witness or his family members. It shall contain specific detail about the nature of threats faced by the witness or his family to their life, reputation or property apart from analyzing the extent, the or persons making the threat have the intent motive and resources to implement the threat.

It shall also categorize the threat perception apart from suggesting the specific witness protection measures which deserves to be taken in the matter;

- (n) **"Witness"** means any person, who possesses information or document about any offences;
- (o) **"Witness Protection Application"** means an application moved by a witness or his family members or his relative or his duly engaged counsel or the concerned investigation officer/SHO/ Jail Superintendent concerned in the prescribed form before the Competent Authority through its member secretary for seeking a Witness Protection Order;
- (p) **"Witness Protection Cell"** means a Cell of district police headed by the Additional Deputy Commissioner of Police/ Additional / Superintendent of Police which is assigned the duty to implement the Scheme ;
State witness protection cell in police Headquarter headed by Additional Director General of Police (crime);
- (q) **"Witness Protection Fund"** means the fund created for bearing the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority under this scheme ;
- (r) **"Witness Protection Order"** means an order passed by the Competent Authority detailing the steps to be taken.

Part-II

3. Categories of Witness as per Threat Perception.-

- Category 'A' : Where the threat extends to life of witness or his family members, during investigation /trial or thereafter.
- Category 'B' : Where the threat extends to safety, reputation property of the witness or his family members during the investigation / trial/ thereafter.
- Category 'C' : Where the threat is moderate and extends to harassment and intimidation of the witness or his family member's reputation or property, during the investigation /trial / thereafter.

4. State Witness Protection Fund .- (1) There shall be a Fund, namely, the Witness Protection Fund from which the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority and other related expenditure shall be met.

(2) The Witness Protection Fund shall comprise the following namely.-

- i. Budgetary allocation made in the Annual Budget;
- ii. Receipt of amount of costs imposed/ordered to be deposited by the courts/ tribunals in the Witness Protection Fund;
- iii. Donations/Contribution from International/ National /Philanthropist/Charitable Institutions/Organization and individuals permitted by the government;
- iv. Fund Contributed under corporate social responsibility.

(3) The said Fund shall be operated by the Department of Home.

5. Filling of Application before Competent Authority .- The application for seeking protection order under this scheme, may be filed, in the prescribed form before the Competent Authority of the concerned district where the offence, is committed through its member secretary along with supporting documents, if any.

6. Procedure for processing the application.-

(a) As and when an application is received by the ,member secretary of the Competent Authority, in the prescribed form, he shall forthwith passed an order for calling the Threat Analysis Report from the Additional Superintendent of police/ Deputy superintendent of

police/ Additional Deputy Commissioner of Police District/ Assistant Commissioner of Police from the police District or SHO of the concerned Police Station;

- (b) Depending upon the urgency in the matter owing to imminent threat, the Competent Authority may pass orders for interim protection of the witness or his family members during the pendency of the application; provided that nothing shall preclude police from providing immediate protection in case of grave and imminent threat to the life of applicant and his family members;
 - (c) The Threat Analysis Report shall be prepared expeditiously while maintaining full confidentiality and it shall reach the Competent Authority within five working days of receipt of the order;
 - (4) The threat analysis report, shall categorize the threat perception and shall also includes the suggestive protection measures for providing adequate protection to the witness or his family.
 - (5) While processing the application for witness protection, the competent Authority shall also interact preferably in person and if not possible through electronic means with the witness and/ or his family members/ employers or any other person deemed fit, so as to ascertain the witness protection needs of the witness.
 - (6) All the hearings on Witness Protection Application shall be held in-camera in the chamber of the Competent Authority while maintaining full confidentiality.
 - (7) An application shall be disposed of within 5 working days of receipt of Threat Analysis Report from the police authorities .
 - (8) The Witness Protection Order passed by the Competent Authority shall be implement by the Witness Protection Cell of the State/District as the case may be. Overall responsibility of implementation of all witness protection orders shall lie on the state witness protection cell , police Headquarter Rajasthan Jaipur.
- However the Witness Protection passed by the Competent Authority for change of identity or/ and relocation shall be implemented by the State Witness Protection cell in police Headquarter with permission of the State Government;
- (i) Upon passing of a Witness Protection Order, the Witness Protection Cell shall file a monthly follow-up report before the Competent Authority;
 - (ii) In cases the Competent Authority finds that there is a need to revise the Witness Protection Order or an application is moved in this regard and upon completion of trial, a fresh Threat Analysis Report shall be called from the Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police/Additional Deputy Commissioner of Police of the District/Assistente of the police from the police District or SHO of the concerned Police Station .

7. Types of protection measures.- The witness protection measures ordered shall be proportional to the threat and shall be for a Specific duration not exceeding three month at time these may include:-

- (a) Ensuring that witness and accused do not come face to face during investigation or trial;
- (b) Monitoring of mail and telephone calls;
- (c) Arrangement with the telephone company to change the witness's telephone number or assign him or her an unlisted telephone number;
- (d) Installation of security devices in the witness's home such as security doors, CCTVs, alarms, fencing etc;
- (e) Concealment of identity of the witness by referring to him/her with the changed name or alphabet;
- (f) Emergency contact persons for the witness;
- (g) Close protection, regular patrolling around the witness's house;
- (h) Temporary change of residence to a relative's house or a nearby town;

(i) Escort to and from the court and provision of Government vehicle or State found conveyance for the date of hearing;

(j) Holding of in-camera trials;

(k) Allowing a support person to remain present during recording of statement and deposition;

(l) Usage of specially designed vulnerable witness court rooms which have special arrangements like live links, one way mirrors and screens apart from separate passages for witnesses and accused, with option to modify the image of face of the witness and to modify the audio feed of the witness's voice, so that he/she is not identifiable;

(m) Ensuring expeditious recording of deposition during trial on day to day basis without adjournments;

(n) Awarding time to time periodical financial aids/grants to the witness from Witness Protection fund for the purpose of re-location, sustenance or starting a new vocation/ profession, as may considered necessary ;

(o) Any other form of protection measures considered necessary.

8. Monitoring and review.—Once the protection order is passed, the Competent Authority shall monitor its implementation and may review the same in terms of follow-up reports received in the matters. However the Competent Authority shall review the Protection order on quarterly bases based on the monthly follow-up report submitted by the Witness Protection Cell.

9. Protection of identity .—(1) During the course of investigation or trial of any offence, an application for seeking identity protection may be filed in the prescribed form of the Competent Authority through its members secretary.

(2) Upon receipt of the application, the members secretary of the Competent Authority shall call for the Threat Analysis Report. The Competent Authority shall examine the witness or his family members or any other it deem fit to ascertain whether there is necessity to pass an identity protection order.

(3) During the course of hearing of the application, the identity of the witness shall not be revealed to any other person, which is likely to lead to the witness identification. The Competent Authority can there after dispose of the application as per material available on record.

(4) Once, an order for Protection of identity of witness is passed by the Competent Authority, it shall be responsibility of Witness Protection Cell to ensure that identity of such witness/his or her family members including/name/parentage/occupation/address/digital foot prints is fully protected.

(5) As long as identity of any witness is protected under an order of the Competent Authority, the Witness Protection Cell shall provide details of persons who can be contacted by the witness in case of emergency.

10. Change of Identity.— in appropriate cases, where there is a request from the witness for Change of identity and based on the Threat Analysis Report a decision can be taken for conferring a new identity to the witness by the Competent Authority.

Conferring new identity includes new name/ profession /parentage and providing supporting document accepting by the government agencies. The new identity should not deprive the witness from existing educational/ professional /property rights .

11. Relocation of Witnesses.— in appropriate cases, where there is a request from the witness for Relocation and based on the Threat Analysis Report, a decision can be taken for Relocation of the witness by the Competent Authority.

The Competent Authority may pass an order for witness Relocation to a safer place within the state/UT or territory of the India union keeping in view the safety, welfare and wellbeing of the witness. The expenses shall be borne by the witness protection fund.

Part VI

12. Witnesses to be apprised of the scheme.- The Investigating Officer/Court shall inform each and every witness about the existence of "Witness Protection Scheme" and its salient features and publicity to this scheme.

13. Confidentiality and preservation of records.- (1) All Stakeholder including the police, prosecution department, Court staff, Lawyer from both sides shall , maintain full confidentiality and shall ensure that under no circumstance, any record, document or information to the proceedings under this scheme shall be shared with any person in any manner except with the Trial Court/Appellate Court and that to on a written order.

(2) All the records pertaining to proceedings under this scheme shall be preserved till such time the related trial or appeal thereof is pending before a Court of Law. After one years of disposal of the last Court proceedings, the hard copy of the records can be weeded out by the Competent Authority after preserving the scanned soft copies of the same.

14. Recovery of expenses.- In case the witness has lodged a false complaint, the State Protection Cell by the permission of the Government can initiate proceedings for recovery of the expenditure incurred from the Witness Protection fund.

15. Review.- In case the witness or the police authorities are aggrieved by the decisions of the Competent Authority, a Review application may be filed within 15 days of passing of the orders by the Competent Authority.

16. Repeal & Saving.- The Rajasthan witness protection scheme 2018 is hereby repealed. The Repeal shall not affect the precious operation of the enactment so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done or taken.

By order of the Governor of Rajasthan
N.L.Meena,
Secretary Home to the Government.

Witness Protection Application under**The Rajasthan Witness Protection Scheme, 2020**

(To be filled in duplicate)

Before,

The Competent Authority,
Rajasthan-----

Application for .

1. Witness Protection
2. Witness, Identity, Protection
3. New, Identity
4. Witnesses Relocation

1- Particulars of the Witness (Fill in Capital):-

(1) Name

(2) Age

- (3) gender (male/female/other)
- (4) Father's /Mother's Name
- (5) Residential Address
- (6) Name and other of family member of the witness who are receiving or perceiving threats
- (7) Contact detail (Mobile/e-mail)

2. Particulars of Criminal matter:-

- (1) FIR No.:-
- (2) Under Section:-
- (3) Police Station:-
- (4) District:-
- (5) D.D. No. (In case FIR not yet registered)
- (6) Cr. Case No. (In case of private complaint)

3. Particulars of the Accused:- (If available/Known)

- (1) Name -----
- (2) Address:- -----
- (3) Phone No
- (4) Email id

4 Name & other particulars of the person giving/suspected of giving threats:-

5. Nature of threat perception.
Please give brief details of threat
Received or perceived in the matter
With specific date, place, mode and word used:-

6. Nature of witness protection
Measures prayed by/for the witness:-

7. Details of Interim urgent Witness
Protection needs, if required.

Witness shall file a separate undertaking under his/her signature that he/she shall fully cooperate with the Competent Authority and Divisional Magistrate /Witness Protection Cell.

Applicant/witness can use extra sheets for giving additional information.

Date:

Place:

(Full Name with signature)

UNDERTAKING

- 1- I under take that I shall fully cooperate with the competent authority and the department of Home the state and Witness protection cell.
- 2- I certify that the information provided by me in this application is true and correct to my best Knowledge and belief .

- 3- I understand that in case, information given by me in this application is found to be false, competent authority under the scheme are reserves the right to recover the expenses incurred on me from out of the Witness protection fund.

Date:

Place:

(Full Name with signature)

Government Central Press, Jaipur.